spent ? Is it not a fact that the staff in DTC not only in Orissa but in other parts of the country is not adequate to cope with the situation ? The hon. Prime Minister has recently introduced employment orientation programme. What steps have been taken to provide adequate staff so that whatever job has been entrusted to the industrial units, they can do immediately ?

MR. SPEAKER : As has been said, fact is a fact and that remains a fact, the hon. Member wants to know, is it a fact that saying and doing are completely two different things.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : Most of the units mentioned in the statement are artisan-based units. The hon. Member would agree that it is not possible for the Central Government to monitor each and every artisan-based unit throughout the country. I have mentioned that regarding the small scale units. There is a Committee set up under the auspices of the Reserve Bank. That is also a State level Committee in which the Directorate of Industry and State Department (Industries) have a major role to play to identify the sick units. There is a State apparatus for the purpose. We have to take the help of this State apparatus. It is not possible for the Centre to operate every unit from here.

SHRI SUNIL MAITRA : The hon. Minister said—fact is fact. I am inviting his attention to the facts brought out by the CAG. This is regarding the audit report for the year 1981-82 pertaining to the District Industries Centres. In this report, the Comptroller and Auditor General of India has stated that in the test checks in every State It has been found out that out of the projects sanctioned, the number of projects have not all come into existence. May I know from the hon. Minister out of this impressive figure of 2,23,000 and odd units sanctioned in Orissa, how many of them are today operational?How many of them have already gone out of existence ? How many are closed down ? How many are sick ?

Your Department at the Centre is the national coordinator of the District Industries Centres. Therefore, the Central Government should be in possession of the facts to ascertain whether out of 2,23,055 units sanctioned in Orissa, how many are functional and how many are not functional.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : Sir, the statement mentions in aggregate those units which are functional. But as of today, if any unit is closed down or sick, of course, all statistics can not be available. Normally, the figures that are given are supposed to be functional units.

As far as the report of the Auditor General is concerned, I am not, at this point of time, aware of any Auditor General's report regarding Orissa. But I will seek information on that.

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 70 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में एक परिपत्र जारी किया था और यह घोषणा की थी प्रत्येक इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में एक एक बड़ा उद्योग पब्लिक सैक्टर में लगायेंगे। मैं जानना चाहता हूं—पिछले चार वर्षों में किन-किन इण्डस्ट्रीयली बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में उद्योग लगाये हैं और इण्डस्ट्रीयली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में किन-किन जिलों के नाम हैं ?

MR. SPEAKER : Next Question.

Manufacture of Paper based on Bagasse

*645. SHRI PITAMBAR SINHA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether there is any plan to manufacture paper based on agasse at Kumarbagh in West Champara b District of Bihar ; and

(b) if so, the details of the Plan ?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) and (b) West Champaran District, Bihar has a cluster of sugar mills which along with the neigbouring areas offer potential for consideration of a bagasse based paper project located at Kumarbagh, Details with regard to availability of raw materials on a sustained basis, supply of coal and power, provision of infrastructural facilitities, and financing pattern would have to be settled before a project can be posed for an investment decision by intending entrepreneurs.

श्री पीताम्बर सिंह : मैं जानना चाहता हूं—सरकार ने लगातार कच्चे माल की उपलब्धि के लिये, कोयला तथा बिजली की आपूर्ति के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की है, जिससे इस उद्योग के वहां खड़ा करने में सहायता मिल सके तथा इस काम में गति आ सके ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : प्रस्ताव यह है कि कुमार बाग को केन्द्र मानकर पश्चिमी चम्पारन जिले में यह प्रयास किया जाय कि बगास के आधार पर अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित किया जा सके ।

प्रस्ताव के अनुसार यह 80 हजार टन कागज प्रति वर्ष उत्पादन करने की मिल होगी और इस में 50 फीसदी अखबारी कागज और 50 फीसदी लिखने और प्रकाशन के हेतु उपयोग होने वाला कागज उत्पादित किया जा सकेगा । यह जो प्रोजेक्ट है, इस का अनुमानित व्यय लगभग 200 करोड़ रु० का आंकलित किया गया है । इस में जो कठिनाइयां हैं, उनमें पहली तो यह है कि सवा तीन लाख मीट्रिक् टन बगास की आवश्यकता होगी और जो वर्तमान काम कर रही चीनी मिलें, हैं उनमें से 6 और 8 मिलों से यह बगास प्राप्त हो सकेगी लेकिन अभी वे उस बगास को अपने वायलरों में उपयोग करती हैं । इसलिए उनको अपने यहां कोल फायर बायलर लगाने होंगे । इस के लिए मिलों को बात के लिए तैयार करना होगा कि वे अपने यहां कोयला इस्तेमाल करें और साथ ही साथ 36 लाख टन मीट्रिक बांस का इन्तजाम करना होगा, जिसमें से 15 हजार मीट्रिक टन तो मिल सकता है और बाकी 20 हजार मीट्रिक टन की कमी है । इसमें साढ़े तीन लाख टन कोयले की आवश्यकता होगी और वहां जो छोटी लाइन है, उस क्षेत्र को बड़ी लाइन जो अब आ गई है, उससे मिलाना होगा कुमार बाग को उस से मिलाना होगा । ये जो कठिनाइयां है, इन के बारे में राज्य सरकार से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट के सामने जो आने वाली कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने हेतु वह प्रयास करे और यह बताए कि राज्य सरकार इस में कितना कुछ कर सकती है । तभी प्रोजेक्ट विचारार्थ प्रस्तुत हो सकेगी । इसमें यह बात भी सामने आएगी कि यह पब्लिक सेक्टर में होगी या प्राइवेट सेक्टर में होगी और कौन इस को बनाएगा ?

श्री पीताम्बर सिंह : सरकार के जवाब से ऐसा लगता है कि सरकार ने अभी तक अपने को आश्वस्त नहीं किया है कि वहां बगास की उचित मात्रा में सुविधा है या नहीं । जो जवाब मैंने देखा है, उस से ऐसा लगता है । मेरी जानकारी में 12 शूगर फैक्टरियां वगल में हैं और मंत्री महोदय का जवाब है कि 6 फैक्टरियों से उपयुक्त मात्रा में बगास उपलब्ध कराने की संभावना हो सकती है । मैं समझता हूं कि वहां पर

सस्टेंड लगातार आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं और उसमें कोई कठिनाई नहीं मालूम होती है।

दूसरी बात आपने कोयले और पावर के बारे में कही और छोटी लाइन के बारे में भी कहा। कोल और पावर अभी भी छोटी लाइन होने पर वहां लोगों को प्राप्त होती है और रेगूलर हो रही है और वगल में जो उद्योग हैं, उन तमाम उद्योगों को कोल सप्लाई हो रहा है और 12 शूगर फैक्टरियां चल रही हैं। उन को जितने कोल की आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति होती है और दूसरे कार्यों के लिए भी कोल की आपूर्ति होती है। ऐसी स्थिति में बड़ी लाइन की शर्त बनाकर इसे मुल्तवी करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया है? जो शर्तें उन्होंने बताई है, उन्हें पूरा करवाने के किए क्या राज्य सरकार को लिखा है ? उन शर्तों को पूरा करने के लिए क्या आपने उन उद्योगपतियों को कहा है, कि उन्हें बोयलर की तकनीक बदलनी है। यह मैं आप से जानना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वहां पर संभावना विद्यमान है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, इसलिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से इस प्रोजेक्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट बनवाई है और यह आशा की जाती है कि यह संभावना साकार हो सकेगी लेकिन इसके लिए जो कठिनाइयां हैं, उनको अगर ध्यान में न रखा जाए, तो फिर इस प्रोजेक्ट का बनाना संभव नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य ने 12 कारखानों का उल्लेख किया है, मगर उन 12 कारखानों में से कौन से कारखाने इसके लिए तैयार होंगे, यह प्रश्न सामने है। दूसरी यह बात है कि इस की कीमत कितनी पड़ेगी। बगास के जो बायलर हैं, उन को बदलना पड़ेगा और उस की सारी कीमत इस प्रोजेक्ट में आएगी। जितने भी चीनी के कारखानों के बायलर बदले जाएंगे, उनकी कीमत इस नये कारखाने के द्वारा देनी होगी। इसलिए उन की स्वीकृति भी आवश्यक है। हमारा यह प्रयास होगा कि इन कठिनाइयों को दूर किया जाए। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान करें, तो यह राज्य सेक्टर में होगा या केन्द्रीय सेक्टर में होगा या प्राइवेट सेक्टर में होगा। इस प्रोजेक्ट में जो कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों की संभावनाओं की अभिव्यक्ति कर के ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री पीताम्बर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि कागज के अभाव को देखते हुए और कागज आप बाहर से मंगा भी रहे है, ऐसी स्थिति में क्या सातवीं योजना में आप इस को स्थान देने आ रहे हैं।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से ऐसा लगता है कि जो खर्च पड़ेगा बायलर बदलने के लिए, उस खर्च को उस फैक्ट्री से जो उद्योग लगना है नया, उसी से करना पड़ेगा। जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस की सुविधा है। तो जितने चीनी उद्योग है, उनको इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वे बैंकों से बायलर बदलने के लिए ऋण लेकर बायलर बदलें और जो बगाज जलावन के काम में लेते हैं उसको बचाकर इस फैक्ट्री में उपयोग करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है लेकिन जिस मिल में काम चल ही रहा है और वे अपने

ही बगाज को अपने बायलर में डाल रहे हैं। ऐसा तमिलनाडु में हो चुका है। तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट में काम हो रहा है जहां पर इस प्रकार बगाज बायलर को बदलकर के कोल फायर बायलर लगाया है। इस तरह से अगर हो सकता है तो बहुत अच्छा है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Nationalisation of Orissa Minerals Development Company Limited

*644. SHRI CHINTAMANI JENA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the management of the Orissa Minerals Development Company Limited has been taken over, if so, when the management was taken over ;

(b) whether there is a demand from the workers that this company should be nationalised for the benefit of workers and Government ;

(c) whether the company is running in losses, if so, the losses incurred during the last three years and the reasons for the losses ; and

(d) Government's proposal in regard to nationalisation of this project ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) The management of the Orissa Minerals Development Company Limited (OMDC) has not been taken over by Government ; it continues to be managed by its Board of Directors. In accordance with provisions of the Bird and Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings and Other Pfoperties Act, 1980) Government acquired only the 85,219 equity shares held in the OMDC by the erstwhile Bird and Company Ltd. out of a total of 9,00,000 equity shares. But with the support of the other shareholders, Government has been able to have four of its nominees elected on the Board out of the total Board membership of five.

(b) Demands were made by workers of the OMDC and others for the nationalisation of the OMDC.

(c) The net profit earned or loss incurred by the company during 1980-81, 1981-82 and 1982-83 was as follows :—

Year*	Profit earned (+) or Loss incurred (—)
1980-81 ...	(—) Rs, 23.59 lakhs
1981-82 ...	(+) Rs. 2.34 lakhs
1982-83 ...	(—) Rs. 56.99 lakhs

* Accounts of the Company are maintained for the period 1st July to 30th June of the following year.

The main reason for the losses incurred by the Company in 1982-83 is the lower off take of iron ore and manganese ore.